



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 11—मई 17, 2019 (वैशाख 21, 1941)
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 11—MAY 17, 2019 (VAISAKHA 21, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	353	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	537	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1179	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 1059
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 21
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 759
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	353	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	537	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1179	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1059
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	21
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	759
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2019

सं. एफ. 10-1/2018-यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय संस्था घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 22.07.2008 की अधिसूचना सं. 9-34/2007-यू.3(ए) के जरिए क्राईस्ट कॉलेज (स्वायत्त), बंगलौर, कर्नाटक, को पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए “क्राईस्ट विश्वविद्यालय” के नाम तथा शैली में सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया था। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार “क्राईस्ट विश्वविद्यालय” के नाम से ‘विश्वविद्यालय’ शब्द का लोप करके “क्राईस्ट” में बदल दिया गया। इसके बाद, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 08.06.2018 की अधिसूचना सं.9-34/2007-यू.3(ए) पार्ट-1 के जरिए क्राईस्ट, बेंगलुरु को कतिपय शर्तों के अध्वधीन तक समविश्वविद्यालय का दर्जा दिनांक 30.06.2019 बढ़ा दिया गया था।

3. और जबकि, क्राईस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक ने दिनांक 15.02.2018 को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एक ऑफ कैम्पस केंद्र शुरू करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। यह आवेदन यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार जांच और सलाह हेतु यूजीसी को अग्रेषित किया था।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी ने प्रस्तावित ऑफ कैम्पस केंद्र पर उपलब्ध अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के स्थल मूल्यांकन हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इसके साथ, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने भी प्रस्तावित ऑफ-कैम्पस के दौरे हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। दोनों समितियों ने दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 को संस्थान का दौरा किया। इस आयोग ने दिनांक 10.12.2018 को आयोजित अपनी 537वीं बैठक (मद सं. 2.02) में विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया और संस्तुति की कि यूजीसी और एआईसीटीई, विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुपालन के अध्वधीन क्राईस्ट (सम-विश्वविद्यालय) बेंगलुरु को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में ऑफ कैम्पस केंद्र शुरू करने के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया जाए।

5. और जबकि, सम-विश्वविद्यालय संस्था ने विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गये सुझावों के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मंत्रालय में अनुपालन रिपोर्ट के अवलोकन के बाद यह पाया गया कि सम-विश्वविद्यालय संस्था ने प्रस्तावित पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक संकाय संख्या की भर्ती कर ली और अवसंरचना का सृजन कर लिया है तथापि, प्रबंधन और विधि पाठ्यक्रमों हेतु एआईसीटीई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से अपेक्षित अनुमोदन अभी प्राप्त किया जाना है।

6. और इसके अतिरिक्त जबकि, मॉडल आचार संहिता के प्रभावी होने के कारण, इस मामले को सहमति/अनुमोदन हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) भेज दिया था। भारतीय निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन अपना अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया था:—

- i. इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, रेडियो, इंटरनेट या किसी अन्य मीडिया में किसी भी रूप में कोई प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा।
- ii. इस संबंध में कोई भी राजनैतिक कार्यकर्ता/प्रेस या जनता को किसी सार्वजनिक भाषण या संवाद में कोई संदर्भ नहीं देगा।

- iii. प्रचार-प्रसार में ये प्रतिबंध केंद्र सरकार के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों पर भी लागू होंगे।
- iv. आयोग द्वारा जारी मॉडल आचार संहिता के संगत प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

7. अब, इसलिए, केंद्र सरकार एतद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर क्राईस्ट (सम-विश्वविद्यालय) बेंगलुरु, कर्नाटक को निम्नलिखित तीन विभागों के साथ गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में ऑफ-कैम्पस केंद्र शुरू करने की अनुमति देती है:—

- i. अर्थशास्त्र विभाग
- ii. मनोविज्ञान विभाग
- iii. वाणिज्य विभाग

8. उपर्युक्त पैरा 7 में दी गई अनुमति आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

- i. यह घोषणा शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से प्रभावी होगी, बशर्ते यदि क्राईस्ट, बेंगलुरु को सम-विश्वविद्यालय दर्जे को 30.06.2019 से आगे बढ़ाया जाता है।
- ii. क्राईस्ट (सम-विश्वविद्यालय), बेंगलुरु गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश कैम्पस में प्रबंधन और विधि के क्षेत्रों में पाठ्यक्रम केवल संबंधित सांविधिक परिषदों के अनुमोदन के बाद शुरू करेगा।
- iii. गाजियाबाद ऑफ-कैम्पस के समग्र कार्य-निष्पादन की निगरानी आयोग द्वारा छह वर्षों तक अर्ध-वार्षिक तौर पर और तदोपरांत मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी और प्रबंधन, शैक्षणिक विकास और सुधार के संबंध में इसके निदेश घटक संस्था पर बाध्यकारी होंगे।
- iv. इस मंत्रालय में विनिर्धारित की गई सभी पूर्व शर्तों का सम-विश्वविद्यालय द्वारा पालन किया जाएगा।
- v. गाजियाबाद कैम्पस को मौजूदा कार्मिक के साथ-साथ सभी चल और अचल आस्तियों/संपत्तियों को क्राईस्ट (सम-विश्वविद्यालय) बेंगलुरु, कर्नाटक के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा।
- vi. यूजीसी की पूर्व अनुमति के बगैर सम-विश्वविद्यालय संस्था/ अथवा इसके ऑफ कैम्पस की निधियों/ राजस्व का कोई विपथन नहीं होगा।
- vii. क्राईस्ट (सम-विश्वविद्यालय) बेंगलुरु, कर्नाटक के साथ-साथ इसके ऑफ कैम्पस ऐसी किसी गतिविधि में शामिल या लिप्त नहीं होंगे जिसकी प्रकृति वाणिज्यिक या लाभकारी हो।
- viii. सम-विश्वविद्यालय संस्था के ऑफ कैम्पस पर प्रस्तावित किए जा रहे/ प्रस्तावित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषदों द्वारा विनिर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप होंगे।
- ix. सम-विश्वविद्यालय संस्था, अपने सभी ऑफ कैम्पस में शोध कार्यक्रम और डॉक्टरल एवं नवाचार शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी।
- x. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नये पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों को शुरू करने आदि के मामले में यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषद के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाविधि लागू रहेंगी और क्राईस्ट (सम-विश्वविद्यालय), बेंगलुरु, कर्नाटक और इसके ऑफ कैम्पसों द्वारा उनका पालन किया जाएगा।
- xi. जैसे और जब भी आवश्यक हो, क्राईस्ट (सम-विश्वविद्यालय), बेंगलुरु, कर्नाटक समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2016 के अनुसार अपने समझौता ज्ञापन (एमओए)/नियमों को अद्यतन या संशोधित या उपांतरित करेंगी।
- xii. क्राईस्ट (सम-विश्वविद्यालय), बेंगलुरु, कर्नाटक समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 में निहित यूजीसी के अनुदेशों का पालन करेगा।

सं. एफ. 10-2/2018-यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय संस्था घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 22.07.2008 की अधिसूचना सं. 9-34/2007-यू.3(ए) के जरिए क्राईस्ट कॉलेज (स्वायत्त), बंगलौर, कर्नाटक, को पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए “क्राइस्ट विश्वविद्यालय” के नाम तथा शैली में सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया था। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार “क्राइस्ट विश्वविद्यालय” के नाम से ‘विश्वविद्यालय’ शब्द का लोप करके “क्राइस्ट” में बदल दिया गया था। इसके बाद, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 08.06.2018 की अधिसूचना सं.9-34/2007-यू.3(ए) पार्ट-3 के जरिए क्राईस्ट, बेंगलुरु को कतिपय शर्तों के अध्यधीन तक सम-विश्वविद्यालय का दर्जा दिनांक 30.06.2019 बढ़ाया गया था।

3. और जबकि, क्राईस्ट, बेंगलुरु कर्नाटक ने दिनांक 15.02.2018 को लवासा (पुणे) महाराष्ट्र में एक ऑफ कैम्पस केंद्र शुरू करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। यह आवेदन यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार जांच और सलाह हेतु यूजीसी को अग्रेषित किया था।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी ने प्रस्तावित ऑफ कैम्पस केंद्र पर उपलब्ध अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के स्थल मूल्यांकन हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इसके साथ, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने भी प्रस्तावित ऑफ-कैम्पस के दौरे हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। दोनों समितियों ने दिनांक 26-27 अक्टूबर, 2018 को संस्थान का दौरा किया। इस आयोग ने दिनांक 10.12.2018 को आयोजित अपनी 537वीं बैठक में विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया और संस्तुति की कि यूजीसी और एआईसीटीई, विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुपालन के अध्यधीन क्राईस्ट (सम-विश्वविद्यालय) बेंगलुरु को लवासा (पुणे) महाराष्ट्र में ऑफ कैम्पस केंद्र शुरू करने के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया जाए।

5. और जबकि, सम-विश्वविद्यालय संस्था ने विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गये सुझावों के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मंत्रालय में अनुपालन रिपोर्ट के अवलोकन के बाद यह पाया गया कि सम विश्वविद्यालय संस्था ने प्रस्तावित पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक संकाय संख्या की भर्ती कर ली और अवसंरचना का सृजन कर लिया है तथापि, प्रबंधन और विधि पाठ्यक्रमों हेतु एआईसीटीई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से अपेक्षित अनुमोदन अभी प्राप्त किया जाना है।

6. और इसके अतिरिक्त जबकि, मॉडल आचार संहिता के प्रभावी होने के कारण, इस मामले को सहमति/अनुमोदन हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) भेज दिया था। भारतीय निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अपना अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया था:—

- i. इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, रेडियो, इंटरनेट या किसी अन्य मीडिया में किसी भी रूप में कोई प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा।
- ii. इस संबंध में कोई भी राजनैतिक कार्यकर्ता/प्रेस या जनता को किसी सार्वजनिक भाषण या संवाद में कोई संदर्भ नहीं देगा।
- iii. प्रचार-प्रसार में ये प्रतिबंध केन्द्र सरकार के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों पर भी लागू होंगे।
- iv. आयोग द्वारा जारी मॉडल आचार संहिता के संगत प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

7. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर क्राईस्ट (सम-विश्वविद्यालय) बेंगलुरु, कर्नाटक को निम्नलिखित तीन विभागों के साथ लवासा (पुणे), महाराष्ट्र में ऑफ-कैम्पस केंद्र शुरू करने की अनुमति देती है:—

- i. अर्थशास्त्र विभाग
- ii. मनोविज्ञान विभाग
- iii. वाणिज्य विभाग

8. उपर्युक्त पैरा 7 में दी गई अनुमति आगे निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:—

- i. यह घोषणा शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से प्रभावी होगी, बशर्ते यदि क्राईस्ट, बेंगलुरु को सम-विश्वविद्यालय दर्जे को 30.06.2019 से आगे बढ़ाया जाता है।

- ii. क्राईस्ट (सम-विश्वविद्यालय), बेंगलुरु लवासा (पुणे), महाराष्ट्र कैम्पस में प्रबंधन और विधि के क्षेत्रों में पाठ्यक्रम केवल संबंधित सांविधिक परिषदों के अनुमोदन के बाद शुरू करेगा।
- iii. लवासा ऑफ-कैम्पस के समग्र कार्य-निष्पादन की निगरानी आयोग द्वारा छह वर्षों तक अर्ध-वार्षिक तौर पर और तदोपरान्त मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी और प्रबंधन, शैक्षणिक विकास और सुधार के संबंध में इसके निदेश घटक संस्था पर बाध्यकारी होंगे।
- iv. इस मंत्रालय में विनिर्धारित की गई सभी पूर्व शर्तों का समविश्वविद्यालय द्वारा पालन किया जाएगा।
- v. लवासा कैम्पस को मौजूदा कार्मिक के साथ-साथ सभी चल और अचल आस्तियों/संपत्तियों को क्राईस्ट (सम विश्वविद्यालय) बेंगलुरु, कर्नाटक के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा।
- vi. यूजीसी की पूर्व अनुमति के बगैर समविश्वविद्यालय संस्था/ अथवा इसके ऑफ कैम्पस की निधियों/ राजस्व का कोई विपथन नहीं होगा।
- vii. क्राईस्ट (सम विश्वविद्यालय) बेंगलुरु, कर्नाटक के साथ-साथ इसके ऑफ कैम्पस ऐसी किसी गतिविधि में शामिल या लिप्त नहीं होंगे जिसकी प्रकृति वाणिज्यिक या लाभकारी हो।
- viii. समविश्वविद्यालय संस्था के ऑफ कैम्पस पर प्रस्तावित किए जा रहे/ प्रस्तावित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषदों द्वारा विनिर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप होंगे।
- ix. समविश्वविद्यालय संस्था, अपने सभी ऑफ कैम्पस में शोध कार्यक्रम और डॉक्टरल एवं नवाचार शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी।
- x. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नये पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों को शुरू करने आदि के मामले में यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषद् के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाविधि लागू रहेंगी और क्राईस्ट (समविश्वविद्यालय), बेंगलुरु, कर्नाटक और इसके ऑफ कैम्पसों द्वारा उनका पालन किया जाएगा।
- xi. जैसे और जब भी आवश्यक हो, क्राईस्ट (समविश्वविद्यालय), बेंगलुरु, कर्नाटक समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2016 के अनुसार अपने समझौता जापन (एमओए)/नियमों को अद्यतन या संशोधित या उपांतरित करेंगी।
- xii. क्राईस्ट (समविश्वविद्यालय), बेंगलुरु, कर्नाटक समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 में निहित यूजीसी के अनुदेशों का पालन करेगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

दिनांक 10 अप्रैल 2019

सं. एफ. 12-26/2010-संस्कृत(यू.3ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, अपनी दिनांक 07.05.2002 की अधिसूचना सं 9-28/2000-यू3 द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली—जिसके लखनऊ, इलाहाबाद, जयपुर, श्रीगैरी, त्रिचूर, पुरी, जम्मू और गारिल (कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश) में स्थित आठ बहु-परिसर को पांच वर्ष के बाद समीक्षा के अधीन “सम-विश्वविद्यालय” के रूप में घोषित किया था। और जबकि, केन्द्र सरकार ने, दिनांक 01.01.2009 की अधिसूचना सं.9-28/2000-यू3 द्वारा, यूजीसी की सलाह पर, ‘राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान’, नई दिल्ली के सम विश्वविद्यालय के दर्जे को अगले पांच वर्षों अर्थात् 06.05.2012 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया था।

3. और जबकि, केन्द्र सरकार ने, यूजीसी की सलाह पर, अपनी दिनांक 30.06.2009 की अधिसूचना सं 9-28/2000-यू3 द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली को भोपाल और मुम्बई परिसर को घटक शिक्षण इकाईयों के रूप में अपने

क्षेत्राधिकार के तहत लाने की अनुमति प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त जबकि, केंद्र सरकार ने दिनांक 13 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या 9-28/2000-यू.3(पार्ट-I) के माध्यम से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के सम-विश्वविद्यालय के दर्जे को दिनांक 07.05.2012 से आगे बढ़ा दिया था।

4. और जबकि, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली ने अगरतला, त्रिपुरा में ऑफ कैम्पस केंद्र शुरू करने के नया आवेदन प्रस्तुत किया था। इस आवेदन को जांच और परामर्श हेतु यूजीसी को अग्रेषित किया था। यूजीसी ने विशेषज्ञ समिति की सहायता से आवेदन की जांच की। आयोग द्वारा दिनांक 22.09.2014 को आयोजित अपनी 503वीं बैठक में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, को अगरतला, त्रिपुरा में ऑफ कैम्पस केंद्र की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव के अनुमोदन की संस्तुति की। इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 दिसंबर, 2016 को यूजीसी की उक्त संस्तुति से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को अवगत करवा दिया था।

5. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श से, एतद्वारा दिनांक 5 दिसंबर, 2016 से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को अगरतला, त्रिपुरा में ऑफ कैम्पस केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करती है।

6. उपर्युक्त पैरा 5 में की गई घोषणा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

- i. अगरतला, त्रिपुरा कैम्पस के समग्र कार्य-निष्पादन की निगरानी आयोग द्वारा छह वर्षों तक अर्ध-वार्षिक तौर पर और तदोपरांत मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी और प्रबंधन, शैक्षणिक विकास और सुधार के संबंध में इसके निदेश घटक संस्था पर बाध्यकारी होंगे।
- ii. इस मंत्रालय में विनिर्धारित की गई सभी पूर्व शर्तों का समविश्वविद्यालय द्वारा पालन किया जाएगा।
- iii. अगरतला, त्रिपुरा कैम्पस को मौजूदा कार्मिक के साथ-साथ सभी चल और अचल आस्तियों/संपत्तियों को सम-विश्वविद्यालय के नाम पंजीकृत किया जाएगा।
- iv. यूजीसी की पूर्व अनुमति के बगैर समविश्वविद्यालय संस्था/अथवा इसके ऑफ कैम्पस की निधियों/राजस्व का कोई विपथन नहीं होगा।
- v. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली के साथ-साथ इसके ऑफ कैम्पस ऐसी किसी गतिविधि में शामिल या लिप्त नहीं होंगे जिसकी प्रकृति वाणिज्यिक या लाभकारी हो।
- vi. समविश्वविद्यालय संस्था के ऑफ कैम्पस पर प्रस्तावित किए जा रहे/प्रस्तावित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषदों द्वारा विनिर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप होंगे।
- vii. समविश्वविद्यालय संस्था अपने सभी ऑफ कैम्पस में शोध कार्यक्रम और डॉक्टरल एवं नवाचार शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी।
- viii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नये पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों को शुरू करने आदि के मामले में यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषद् के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाविधि लागू रहेंगी और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली के साथ-साथ इसके ऑफ कैम्पसों द्वारा उनका पालन किया जाएगा।
- ix. जैसे और जब भी आवश्यक हो, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 के अनुसार अपने समझौता ज्ञापन (एमओए)/नियमों को अद्यतन या संशोधित या उपांतरित करेंगी।
- x. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली के साथ-साथ इसके ऑफ कैम्पस समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 में निहित यूजीसी के अनुदेशों का पालन करेगा।

ईशिता राय
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 8th April 2019

No. F.10/1/2018-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-34/2007-U3(A) dated 22.07.2008, on the advice of UGC, had declared Christ College (Autonomous), Bangalore, Karnataka as an Institution deemed to be University in the name & style of 'Christ University' for the provisional period of five years. Further, pursuant to the direction of Hon'ble Supreme Court, the name of 'Christ University' has been changed to 'Christ' by deleting the word 'University' from its name. Subsequently, on the advice of UGC, the Central Government, vide its Notification No. 9-34/2007-U3(A)Pt.1 dated 08.06.2018, extended the deemed to be University status to Christ, Bengaluru upto 30.06.2019 with certain conditions.

3. And whereas, Christ, Bengaluru, Karnataka submitted an application on 15.02.2018 for starting of an Off-Campus Centre at Ghaziabad, Uttar Pradesh. The application was forwarded to UGC for examination and advice as per the provisions of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

4. And further whereas, UGC constituted an Expert Committee for on the spot assessment of the infrastructure and other facilities available at the proposed Off-Campus Centre. Simultaneously, All India Council for Technical Education (AICTE) also constituted an Expert Committee to visit the proposed Off-Campus. Both the Committees visited the Institute on 24.10.2018. The Commission, in its 537th meeting (Item No.2.02) held on 10.12.2018, considered the reports of Expert Committees and recommended that Letter of Intent (LoI) may be issued to the Christ (Deemed to be University), Bengaluru for starting of an Off-Campus Centres at Ghaziabad (Uttar Pradesh) subject to the compliance of the suggestions given by UGC and AICTE Expert Committee.

5. And whereas, the Institution deemed to be University submitted compliance report w.r.t. suggestions given by the Expert Committee. After perusal of the Compliance report in the Ministry, it has been noted the Institution deemed to be University has recruited the required number of faculty and created the infrastructure for the proposed Courses, however, the requisite approval of the AICTE and Bar Council of India for Management and Law Courses is yet to be obtained.

6. And further whereas, taking into consideration the enforcement of Model Code of Conduct, the matter was referred to the Election Commission of India (ECI) for their concurrence /approval. Election Commission of India conveyed its NOC subject to the following conditions:—

- i. Absolutely no publicity in this regard in electronic, print, radio, internet or any other media, in any form whatsoever.
- ii. No political functionary shall make any reference in this regard during any public speech or communication to the press or public.
- iii. These restrictions on publicity will be applicable to the Central Government as well as the State Governments concerned.
- iv. The relevant provisions of Model Code of Conduct issued by the Commission shall be strictly followed.

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, taking into account the advice of the UGC, hereby permit Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka for starting of an Off-Campus Centre at Ghaziabad, Uttar Pradesh with the following three Departments:—

- i. Department of Economics
- ii. Department of Psychology
- iii. Department of Commerce

8. The permission given in Para 7 above is further subject to the following conditions:—

- i. This declaration shall be effective from the academic year 2019-20 provided that the status of Deemed to be University of Christ, Bengaluru is extended beyond 30.06.2019.
- ii. Christ (Deemed to be University), Bengaluru shall start Courses in the fields of Management & Law at the Ghaziabad Campus only after approval of the respective Statutory Councils.
- iii. The over-all performance of Ghaziabad Campus shall be monitored by the Commission biennially for six years and subsequently as per the provisions of the existing Regulations and whose directions on management, academic development and improvement shall be binding on the Constituent Institution.

- iv. All the earlier conditions that were stipulated in this Ministry's Notifications shall be adhered to by the Institution deemed to be University.
- v. The entire moveable and immovable assets/properties as well as the existing manpower of the Ghaziabad Campus shall be registered in the name of Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka.
- vi. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed-to-be-University/or of its Off-Campus(es), without prior permission of the UGC.
- vii. Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka as well as its Off-Campus(es) shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- viii. The academic programmes offered/to be offered at the Off-Campus(es) of the Institution deemed to be University shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and other Statutory Councils concerned.
- ix. The Institution deemed to be University shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes at all its Off-Campuses.
- x. All the prescribed norms and procedures of the UGC and other Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka and its Off-Campus(es).
- xi. As and when necessary, Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka shall update or revise or modify its Memorandum of Association (MoA) / Rules in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.
- xii. Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka shall adhere to the instructions of the UGC as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019, as amended from time to time.

ISHITA ROY
Joint Secretary

No. F.10/2/2018-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-34/2007-U3 (A) dated 22.07.2008, on the advice of UGC, had declared Christ College (Autonomous), Bangalore, Karnataka as an Institution deemed to be University in the name & style of 'Christ University' for the provisional period of five years. Further, pursuant to the direction of Hon'ble Supreme Court, the name of 'Christ University' has been changed to 'Christ' by deleting the word 'University' from its name. Subsequently, on the advice of UGC, the Central Government, vide its Notification No. 9-34/2007-U3(A)Pt.1 dated 08.06.2018, extended the deemed to be University status to Christ, Bengaluru upto 30.06.2019 with certain conditions.

3. And whereas, Christ, Bengaluru, Karnataka submitted an application on 15.02.2018 for starting of an Off-Campus Centre at Lavasa (Pune), Maharashtra. The application was forwarded to UGC for examination and advice as per the provisions of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

4. And further whereas, UGC constituted an Expert Committee for on the spot assessment of the infrastructure and other facilities available at the proposed Off-Campus Centre. Simultaneously, All India Council for Technical Education (AICTE) also constituted an Expert Committee to visit the proposed Off-Campus. Both the Committees visited the Institute on 26-27th October, 2018. The Commission, in its 537th meeting held on 10.12.2018, considered the reports of Expert Committees and recommended that Letter of Intent (LoI) may be issued to the Christ (Deemed to be University), Bengaluru for starting of an Off-Campus Centres at Lavasa (Pune), Maharashtra subject to the compliance of the suggestions given by UGC and AICTE Expert Committee.

5. And whereas, the Institution deemed to be University submitted compliance report w.r.t. suggestions given by the Expert Committee. After perusal of the Compliance report in the Ministry, it has been noted the Institution deemed to be University has recruited the required number of faculty and created the infrastructure for the proposed Courses, however, the requisite approval of the AICTE and Bar Council of India (BCI) for Management and Law Courses is yet to be obtained.

6. And further whereas, taking into consideration the enforcement of Model Code of Conduct, the matter was referred to the Election Commission of India (ECI) for their concurrence /approval. Election Commission of India conveyed its NOC subject to the following conditions:—

- i. Absolutely no publicity in this regard in electronic, print, radio, internet or any other media, in any form whatsoever.

- ii. No political functionary shall make any reference in this regard during any public speech or communication to the press or public.
- iii. These restrictions on publicity will be applicable to the Central Government as well as the State Governments concerned.
- iv. The relevant provisions of Model Code of Conduct issued by the Commission shall be strictly followed.

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, taking into account the advice of the UGC, hereby permit Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka for starting of an Off-Campus Centre at Lavasa (Pune), Maharashtra with the following three Departments:

- i. Department of Economics
- ii. Department of Psychology
- iii. Department of Commerce

8. The permission given in Para 7 above is further subject to the following conditions:

- i. This declaration shall be effective from the academic year 2019-20 provided that the status of Deemed to be University of Christ, Bengaluru is extended beyond 30.06.2019.
- ii. Christ (Deemed to be University), Bengaluru shall start Courses in the fields of Management & Law at the Lavasa (Pune), Maharashtra Campus only after approval of the respective Statutory Councils.
- iii. The over-all performance of Lavasa Off-Campus shall be monitored by the Commission biennially for six years and subsequently as per the provisions of the existing Regulations and whose directions on management, academic development and improvement shall be binding on the Constituent Institution.
- iv. All the earlier conditions that were stipulated in this Ministry's Notifications shall be adhered to by the Institution deemed to be University.
- v. The entire moveable and immovable assets/properties as well as the existing manpower of the Lavasa Campus shall be registered in the name of Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka.
- vi. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed-to-be-University/or of its Off-Campus (es), without prior permission of the UGC.
- vii. Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka as well as its Off-Campus(es) shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- viii. The academic programmes offered/to be offered at the Off-Campus(es) of the Institution deemed to be University shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and other Statutory Councils concerned.
- ix. The Institution deemed to be University shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes at all its Off-Campuses.
- x. All the prescribed norms and procedures of the UGC and other Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka and its Off-Campus(es).
- xi. As and when necessary, Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka shall update or revise or modify its Memorandum of Association (MoA) / Rules in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.
- xii. Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka shall adhere to the instructions of the UGC as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019, as amended from time to time.

ISHITA ROY
Joint Secretary

The 10th April 2019

No. F.12-26/2010-Skt.(U.3A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-28/2000-U.3 dated 07.05.2002, on the advice of UGC, had declared Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi consisting of its eight multi-campus located at Lucknow, Allahabad, Jaipur, Sringeri, Trichur, Puri, Jammu & Garil (Kangra, Himachal Pradesh) as an “Institution Deemed to be University”, subject to a review after five years. And further whereas, the Central Government, vide Notification No. 9-28/2000-U.3 dated 01.01.2009, on the advice of the UGC, extended the status of Deemed to be University of Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi for a further period of five years i.e. upto 06.05.2012.

3. And whereas, the Central Government, vide Notification No. 9-28/2000-U.3 dated 30.06.2009, on the advice of the UGC, permitted Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed to be University), New Delhi to bring the Bhopal and Mumbai Campus under its ambit as constituent teaching units. And further whereas, the Central Government, vide its Notification No. 9-28/2000-U3(Pt.1) dated 13th February, 2019, extended the status of Deemed to be University of Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi from 07.05.2012 onwards.

4. And whereas, Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi submitted an application for starting of an Off-Campus Centre at Agartala, Tripura. The application was forwarded to UGC for examination and advice. UGC examined the application with the help of its Expert Committee. The report of Expert Committee was considered by the Commission in its 503rd meeting held on 22.09.2014 and recommended for approval the proposal for establishing of off-Campus centre of Rashtriya Sanskrit Sansthan at Agartala, Tripura. The said recommendation of UGC was conveyed to Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi by this Ministry on 5th December, 2016.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby accord its approval on the proposal of Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi to establish an Off-Campus Centre at Agartala, Tripura w.e.f. 5th December, 2016.

6. The declaration, as made in Para 5 above, is further subject to the following conditions:—

- i. The over-all performance of Agartala (Tripura) Campus shall be monitored by the Commission biennially for six years and subsequently as per the provisions of the existing Regulations and whose directions on management, academic development and improvement shall be binding on the Constituent Institution.
- ii. All the earlier conditions that were stipulated in this Ministry's Notifications shall be adhered to by the Institution deemed to be University.
- iii. The entire moveable and immovable assets/properties as well as the existing manpower of the Agartala (Tripura) Campus shall be registered in the name of the deemed to be University.
- iv. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed-to-be-University/or of its Off-Campus(es), without prior permission of the UGC.
- v. Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed to be University), New Delhi as well as its Off-Campus(es) shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- vi. The academic programmes offered/to be offered at the Off-Campus(es) of the Institution deemed to be University shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and other Statutory Councils concerned.
- vii. The Institution deemed to be University shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes at all its Off-Campuses.
- viii. All the prescribed norms and procedures of the UGC and other Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed to be University), New Delhi and its Off-Campus(es).
- ix. As and when necessary, Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed to be University), New Delhi shall update or revise or modify its Memorandum of Association (MoA) / Rules in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019, as amended from time to time.
- x. Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed to be University), New Delhi shall adhere to the instructions of the UGC as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

ISHITA ROY
Joint Secretary